Drishti IAS

करेंट अफेयर्स राजस्थान

अक्तूबर 2023 (संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

राजस्थान **3**

- ➢ मंत्रिमंडल ने राजस्थान वक्फ नियम- 2023 का किया अनुमोदन 3
- ➢ राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन नीति को कैबिनेट से मिली मंज़ूरी 4
- ➢ राजस्थान धरोहर संग्रहालय के प्रथम चरण का लोकार्पण 5
- ➢ राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पोरेशन (RLSDC) का होगा गठन 6
- ➢ मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया स्वीप प्रदर्शनी का उद्घाटन 7
- ➢ जयपुर, बीकानेर, अजमेर एवं जैसलमेर में पैनोरमा के लिये 18 करोड़ रुपए मंज़ूर 7
- ➢ राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा तैयार श्रव्य-दृश्य रिकॉर्डिंग का हुआ लोकार्पण 9
- ➢ राविरा के 127वें अंक का विमोचन 10
- ➢ प्रदेश में रेबीज उन्मूलन हेतु स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च 10
- ➢ प्रदेश को मिले 100 नए फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल 11
- ➢ प्रधानमंत्री ने जोधपुर में लगभग 5000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी 12
- ➢ प्रदेश में होगा 'राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम' 13
- ➢ संक्रामक रोग संस्थान जोधपुर का होगा उन्नयन 14
- ➢ राज्य में 7 बृहद् जलापूर्ति परियोजनाओं के लिये 21 हज़ार 613 करोड़ रुपए स्वीकृत 15
- ➢ राजस्थान घटनाक्रम 15
- ➢ राज-सिलिकोसिस पोर्टल में AI आधारित चेस्ट x-ray ऐप्लीकेशन का शुभारंभ 17
- ➢ मुख्यमंत्री ने 8 बोर्ड के गठन को दी मंज़ूरी 18
- ➢ राजस्थान में होगा जाति आधारित सर्वेक्षण 19
- ➢ राज्य में विधानसभा चुनाव-2023 का कार्यक्रम घोषित 19
- ➢ प्रदेश में पहली बार अनिवार्य सेवाओं की कैटेगरी में मीडियाकर्मी शामिल 20
- ➢ राजस्थान में पहली बार पात्र मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा 21
- ➢ प्रदेश में जुनोटिक डिजीज कंट्रोल हेतु बनेगा 'स्टेट वन-हेल्थ एक्शन प्लान' 22
- ➢ राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर मिला 'टोबेको कंट्रोल एक्सीलेंस अवॉर्ड' 23
- ➢ मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लॉन्च किया 'सहज भीलवाड़ा' ऐप 24
- ➢ राजस्थान पत्रिका के अरुण, मुंडियार व पारीक को मिला 'लाडली मीडिया अवॉर्ड' 25
- ➢ सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान - 'असुरक्षित स्पर्श'पर जागरूकता का दूसरा चरण 28 अक्तूबर को 26
- ➢ विभिन्न क्षेत्रों की 10 प्रभावशाली महिलाओं को राज्यपाल ने किया सम्मानित 27
- ➢ मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनावों के लिये अपनी 5 बड़ी गारंटी लॉन्च करने की घोषणा की 28

नोट :

राजस्थान

मंत्रिमंडल ने राजस्थान वक्फ नियम- 2023 का किया अनुमोदन

चर्चा में क्यों ?

2 अक्तूबर, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान वक्फ नियम-2023 का अनुमोदन कर दिया। इन नियमों के लागू होने से राज्य में वक्फ कार्य अधिक सुगमता, स्पष्टता एवं पारदर्शिता के साथ संपादित हो सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वक्फ अधिनियम-1995 की धारा 109 में वक्फ के संचालन के लिये नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है। राज्य सरकार ने तत्परता दिखाते हुए नियम लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
- राजस्थान वक्फ नियम-2023 में वक्फ संपत्तियों के मुतवल्ली, प्रबंध कमेटी और प्रबंध योजना के साथ ही मुतवल्ली की शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख किया गया है। साथ ही वक्फ सर्वे आयुक्त की नियुक्ति, सर्वे आयुक्त को जाँच की शक्तियाँ एवं वक्फ संपदाओं की सूची के प्रकाशन से संबंधित प्रावधान किये गए हैं।
- इसी प्रकार नियमों में वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, पदावधि और सेवा संबंधी प्रावधानों के साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को किसी भी लोक कार्यालय में किसी वक्फ संपत्ति से संबंधित अभिलेख, रजिस्टर या दस्तावेज़ों के निरीक्षण का अधिकार दिया गया है।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्ड की कार्यवाहियों या अभिरक्षा में रखे अभिलेखों के निरीक्षण की आज्ञा निर्धारित फीस एवं शर्तों के अधीन रहते हुए दे सकेंगे। वहीं अस्तित्व में नहीं रहे ओकाफ (वक्फ संपत्तियों) की जाँच के लिये नियम बनाया गया है। वक्फ संपत्ति के प्रशासन से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर बोर्ड द्वारा जाँच कराए जाने का प्रावधान भी किया गया है।
- राजस्थान वक्फ नियम-2023 में वक्फ जायदादों के लेखों के अंकेक्षण, वक्फ संपत्ति के बिना बोर्ड की अनुमति अंतरित की गई संपत्ति को वापस लेने, संपत्तियों से अतिक्रमण हटवाने, बोर्ड के विरुद्ध किसी भी वाद में पैरवी के लिये वक्फ बोर्ड अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्राधिकृत करने तथा बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट संबंधी प्रावधान भी किये गए हैं।

प्रधानमंत्री ने चित्तौड़गढ़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित की

चर्चा में क्यों ?

2 अक्तूबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया।

प्रमुख बिंदु

- इन परियोजनाओं में मेहसाणा-भटिंडा-गुरदासपुर गैस पाइपलाइन, आबू रोड में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) का एलपीजी संयंत्र, अजमेर बॉटलिंग प्लांट मं् अतिरिक्त भंडारण, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), रेलवे और सड़क परियोजनाएँ, नाथद्वारा में पर्यटन सुविधाएँ और कोटा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का स्थायी परिसर शामिल है।
- गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये प्रधानमंत्री ने मेहसाणा-भटिंडा- गुरदासपुर गैस पाइपलाइन को समर्पित किया। पाइपलाइन का निर्माण लगभग 4500 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है।

नोट :

- प्रधानमंत्री ने आबू रोड में एचपीसीएल के एलपीजी संयंत्र का भी लोकार्पण किया। यह संयंत्र प्रति वर्ष 86 लाख सिलेंडरों का सीलबंद और वितरण करेगा। इससे प्रति वर्ष सिलेंडर ले जाने वाले ट्रकों के संचालन में लगभग 0.75 मिलियन किमी की कमी आएगी, जिससे प्रति वर्ष लगभग 0.5 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी।
- उन्होंने आईओसीएल के अजमेर बॉटलिंग संयंत्र में अतिरिक्त भंडारण का भी लोकार्पण किया।
- प्रधानमंत्री ने एनएच-12 (नया एनएच-52) पर दाराह-झालावाड़-तीनधार खंड पर 4-लेन सड़क का लोकार्पण किया। इसके निर्माण पर 1480 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। यह परियोजना कोटा और झालावाड़ ज़िलों से खदानों से निकलने वाले संसाधनों के परिवहन को आसान बनाएगी।
- इसके अतिरिक्त सवाई माधोपुर में रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) को दो लेन से चार लेन तक बनाने और चौड़ा करने की आधारशिला भी रखी जाएगी। इस परियोजना से वाहनों की आवाजाही सुगम होगी।
- प्रधानमंत्री ने चित्तौड़गढ़-नीमच रेलवे लाइन और कोटा-चित्तौड़गढ़ विद्युतीकृत रेलवे लाइन के दोहरीकरण से जुड़ी परियोजनाएँ राष्ट्र को समर्पित कीं। इन परियोजनाओं पर 650 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। इससे क्षेत्र में रेल बुनियादी ढांचा सुदृढ़ होगा और राजस्थान में ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- प्रधानमंत्री ने 'स्वदेश दर्शन योजना'के अंतर्गत नाथद्वारा में विकसित पर्यटन सुविधाओं का लोकार्पण किया। नाथद्वारा संत वल्लभाचार्य द्वारा प्रचारित पुष्टिमार्ग के लाखों अनुयायियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। नाथद्वारा में एक आधुनिक 'पर्यटक विवेचना एवं सांस्कृतिक केंद्र' विकसित किया गया है, जहाँ पर्यटक श्रीनाथजी के जीवन के विभिन्न पहलुओं का अनुभव कर सकते हैं।
- प्रधानमंत्री ने कोटा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का स्थायी परिसर भी राष्ट्र को समर्पित किया।

राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन नीति को कैबिनेट से मिली मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

1 अक्तूबर, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नई ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- इस नीति के प्रावधानों के अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की स्वीकृति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय सक्षम समिति जारी करेगी।

नोट :

- ग्रीन हाइड्रोजन नीति का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य में 2000 केटीपीए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन है।
- इसके अलावा इस नीति का उद्देश्य है कि रिफाइनरी एवं फर्टिलाइजर प्लांटों की मांग की पूर्ति के लिये न्यूनतम एक ग्रीन हाइड्रोजन वैली की स्थापना की जाए। कम से कम एक गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना के साथ ही भारत से ग्रीन हाइड्रोजन के निर्यात का न्यूनतम 20 फीसदी राजस्थान से आपूर्ति हो तथा राज्य में उत्पादित नेचुरल गैस में 10 फीसदी तक ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग है।
- नई ग्रीन हाइड्रोजन नीति के अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिये अक्षय ऊर्जा प्लांट स्थापना के लिये भूमि का आवंटन भू राजस्व नियम 2007 के अनुसार किया जाएगा। हाइड्रोजन प्लांट के लिये भूमि औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा आवंटित की जाएगी। इसके अलावा निजी भूमि पर भी प्लांट स्थापित किया जा सकता है।
- ग्रीन हाइड्रोजन नीति में यह मिलेंगे प्रोत्साहन-
  - नीति में राजस्थान इन्वेस्टमेंट एवं प्रमोशन स्कीम के अनुसार लाभ देय होंगे। जल की उपलब्धता एवं अक्षय ऊर्जा उत्पादन का एक तिहाई बैंकिंग सुविधा भी मिलेगी।
  - ग्रीन हाइड्रोजन के लिये अक्षय ऊर्जा प्लांट की क्षमता को कॉन्ट्रैक्ट डिमांड से 2.5 गुना तक अनुमत किया जाएगा।
  - प्लांट स्थापना पर प्रसारण एवं वितरण शुल्क में 10 वर्ष तक 50 फीसदी की छूट मिलेगी।
  - तीसरे पक्ष से अक्षय ऊर्जा क्रय करने पर अतिरिक्त एवं क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज में 10 वर्षों तक छूट मिलेगी।
  - ब्रायन वाटर या ट्रीटेड वाटर से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन पर राजकीय भूमि आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी।
  - ग्रीन हाइड्रोजन उपकरण निर्माण की यूनिट के लिये राजस्थान इन्वेस्टमेंट एवं प्रमोशन स्कीम के अनुसार देय लाभ मिलेगा।
  - अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिये लागत का 30 फीसदी अनुदान (अधिकतम 5 करोड रुपए तक) मिलेगा।
  - आरवीएनएल के नेटवर्क पर स्थापित होने वाले प्रथम 500 केटीपीए तक अक्षय ऊर्जा संयंत्र को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा (प्रत्येक प्लांट की अधिकतम 50 विभाग मेगावाट क्षमता तक)।

राजस्थान धरोहर संग्रहालय के प्रथम चरण का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

1 अक्तूबर, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाहर कला केंद्र में आयोजित पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ संवाद कार्यक्रम में राजस्थान धरोहर संग्रहालय के प्रथम चरण के लोकार्पण सहित पर्यटन तथा कला, साहित्य एवं संस्कृति विभाग के लगभग 110 करोड़ रुपए के 25 कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय के साथ ही हैप्पीनेस इंडेक्स में वृद्धि हो और प्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी बने। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा मिशन-2030 के तहत विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, जिसे आगामी 5 अक्तूबर को जारी किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा दूरगामी सोच के साथ कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, इससे पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ा है। साथ ही इस इंडस्ट्री से जुड़ी इकाइयों के लिये अरबन टैक्स 80 प्रतिशत एवं विद्युत शुल्क 30 प्रतिशत कम हो गया है।
- राज्य सरकार ने पर्यटन विकास कोष की राशि बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दी है। इसमें आने वाले वक्त में और वृद्धि की जाएगी।
- उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन के नये-नये क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। सवाई मानसिंह टाउन हॉल में स्थापित राजस्थान धरोहर संग्रहालय राज्य के पर्यटन क्षेत्र में एक और नई कड़ी है। कोटा में चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजोन पार्क का ऐतिहासिक कार्य हुआ है। इससे बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक हाड़ौती क्षेत्र में आएंगे।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास में राज्य उत्तर भारत में नंबर वन और देश में दूसरे स्थान पर है। विगत 5 वर्षों में राज्य की जीडीपी 6 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यह 15 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। वर्ष 2030 तक इसे 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक तक ले जाने का लक्ष्य है।

नोट :

- राज्य में बेहतर माहौल की वजह से निवेशक यहां आना पसंद कर रहे हैं। वर्तमान में राज्य में लगभग सभी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाएँ मौजूद हैं। विश्वविद्यालयों की संख्या भी बढ़कर 90 से अधिक हो चुकी है। प्रदेश में लगभग 1.50 लाख किलोमीटर लंबाई की सड़कें बन रही हैं।

राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पोरेशन (RLSDC) का होगा गठन

चर्चा में क्यों ?

1 अक्तूबर, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में प्लेसमेंट एजेंसियों से लगे कार्मिकों को शोषण से मुक्त करवाने के लिये राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पोरेशन (RLSDC) का गठन किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- हर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिये राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ निर्णय कर रही है। इसी क्रम में प्लेसमेंट एजेंसियों से लगे कार्मिकों को शोषण से मुक्त करवाने के लिये राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलिवरी कॉर्पोरेशन (RLSDC) का गठन किया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा इस सरकारी कंपनी के गठन से प्रदेश में प्लेसमेंट एजेंसियों से कार्मिक लगाने की प्रथा बंद हो जाएगी, जिससे कार्मिकों को शोषण से मुक्ति मिलेगी।
- रेक्सको की तर्ज पर गठित होने वाली आरएलएसडीसी कंपनी से प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से राजकीय विभागों एवं अर्द्ध शासकीय संस्थानों में नियुक्त किये जाने वाले कार्मिकों को बड़ी राहत मिलेगी।
- नई कंपनी के माध्यम से कुशल-अकुशल अभ्यर्थियों का पंजीकरण एवं चयन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा तथा उन्हें बिना अनावश्यक कटौती के उचित पारिश्रमिक मिल सकेगा। प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध होने से कार्यों में अधिक गति आएगी।
- मंत्रिमंडल के निर्णय से एक जनवरी, 2021 से पूर्व के कार्यरत कर्मियों को आरएलएसडीसी के माध्यम से आवश्यकतानुसार सीधे ही लिया जाएगा।
- आरएलएसडीसी कंपनी अधिनियम-2013 के अंतर्गत पंजीकृत शत-प्रतिशत राज्य सरकार के स्वामित्व की कंपनी होगी।
- प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन स्थापित इस कंपनी के अध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग होंगे। साथ ही कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग व श्रम विभाग के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, वित्त व्यय विभाग के शासन सचिव, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निदेशक और राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

नोट :

मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया स्वीप प्रदर्शनी का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

30 सितंबर, 2023 को भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय और अरुण गोयल ने जयपुर के राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा में निर्वाचन विभाग की ओर से लगाई स्वीप प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- प्रदर्शनी में बाड़मेर की 200 फीट लंबी जागरूकता मतदाता फड़ ने जहाँ हर किसी का ध्यान खींचा, वहीं युवाओं और नव मतदाताओं को जागरूक करने के लिये खासतौर पर ELC क्लब कार्टून्स और वर्चुअल रियलिटी का सहारा लिया गया।
- दिव्यांगकर्मियों द्वारा संचालित आदर्श मतदान केंद्र, स्वीप के थैमेटिक पैनल एग्जिबिशन, सेंड आर्ट एगि जिबशन और पेंटिंग गैलरी आकर्षण का केंद्र रहे।
- केंद्रीय संचार ब्यूरो के बुनकर समूह के द्वारा मतदान को प्रेरित करने हेतु तैयार किये गए स्याही लगी अंगुली के निशान ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।
- सतरंगी सप्ताह के तहत 7 थैमेटिक पोस्टर्स का विमोचन किया गया। नए वोटर्स को एपिक कार्ड वितरित किये गए। निर्वाचन विभाग के आइकॉन्स और बेहतरीन कार्य करने वाले कार्मिकों का सम्मान किया गया।
- कार्यक्रम में 'मैं भारत हूँ'गाने को राजस्थान बैकड्रॉप में लॉन्च किया गया, जिसे दिव्यांग बच्चों ने साइन लैंग्वेज में प्रस्तुत किया। बारां के सहरिया आदिवासियों ने 4 मिनट के शानदार नृत्य की प्रस्तुति दी। जैसलमेर के मांगणियार और अजमेर से कालबेलिया डांस की प्रस्तुति ने भी सबका मन मोह लिया।
- प्रदर्शनी में विभिन्न ज़िलों में संचालित की जा रही स्वीप गतिविधियों को खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया। साथ ही स्वीप गतिविधियों में प्रयुक्त विभिन्न प्रचार सामग्रियों को भी आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया गया।

जयपुर, बीकानेर, अजमेर एवं जैसलमेर में पैनोरमा के लिये 18 करोड़ रुपए मंज़ूर

चर्चा में क्यों ?

- 3 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 ज़िलों- जयपुर, बीकानेर, अजमेर एवं जैसलमेर में पैनोरमा निर्माण के लिये 18 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि राज्य सरकार प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं महापुरुषों के जीवन आदर्शों से नई पीढ़ी को अवगत कराने के लिये पैनोरमा तैयार करा रही है।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्वीकृति से जयपुर में स्वामी आत्मारामजी लक्ष्य पैनोरमा तथा बीकानेर में राव बीकाजी पैनोरमा बनेगा। इनमें 4-4 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
- साथ ही, अजमेर में पृथ्वीराज चौहान पैनोरमा तथा जैसलमेर के पोकरण में इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा का निर्माण होगा। इनमें 5-5 करोड़ रुपए व्यय होंगे। सभी कार्य पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन विकास कोष से करवाए जाएंगे।
- इन पैनोरमा में स्वामी आत्माराम जी, पृथ्वीराज चौहान तथा राव बीकाजी के व्यक्तित्व एवं भारत के स्वर्णिम इतिहास के बारे में नई पीढ़ी को जानकारी मिलेगी। इससे वे महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने के साथ ही गौरवशाली इतिहास एवं संस्कृति से परिचित हो सकेंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने इस संबंध में बजट 2023-24 में घोषणा की थी।

नोट :

नोट :

राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा तैयार श्रव्य-दृश्य रिकॉर्डिंग का हुआ लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

- 3 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के कला, साहित्य एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने अपने राजकीय आवास पर राजस्थान संस्कृत अकादमी के तत्वावधान में वेद संरक्षण योजनांतर्गत अकादमी द्वारा अथर्ववेद एवं सामवेद की संपूर्ण संहिता की श्रव्य-दृश्य प्रस्तुति (रिकॉर्डिंग) का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- इस रिकॉर्डिंग को जनसामान्य के लिये सोशल मीडिया वेबसाइट पर प्रसारित किया जाएगा। इसका उद्देश्य वेदों में निहित जन-कल्याण की भावना को जन-जन तक पहुँचाना है एवं वेद पाठ की लुप्त होती स्वर पाठ परंपरा को संरक्षित रखना है।
- इस मौके पर डॉ. सरोज कोचर, अध्यक्ष संस्कृत अकादमी ने वेदों की गुरु परंपरा के संरक्षण हेतु अकादमी द्वारा इस वर्ष बजट घोषणा-23 के अंतर्गत 10 नवीन ज़िलों में वेदाश्रम खोले जाने की जानकारी दी तथा यह भी बताया कि वर्तमान में राज्य के 45 वेदाश्रम अकादमी द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।
- अकादमी निदेशक डॉ. राजकुमार जोशी ने बताया कि अकादमी द्वारा निम्बाहेड़ा में चारों वेदों की 11 शाखाओं के अध्ययन को अकादमी स्तर पर प्रारंभ कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

नोट :

रावित्रा के 127वें अंक का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

4 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने रावित्रा पत्रिका के 127वें संस्करण का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- राजस्व मंडल की ओर से प्रकाशित इस महत्त्वपूर्ण अंक में राजस्व न्यायालयों की बेहतरी को लेकर विशेष लेख, राज्य में नवगठित संभाग, ज़िले, उपखंड व तहसीलों से संबंधित अधिसूचनाओं, राजस्व मंडल न्यायालय के स्तर से पारित श्रेष्ठ निर्णयों को विषय-वस्तु के रूप में समाहित किया गया है।
- इसके साथ ही राजस्व प्रशासन व राजस्व विषय-विशेषज्ञों के माध्यम से महत्त्वपूर्ण विषयों पर लिखे गए आलेख, सरकार द्वारा जारी महत्त्वपूर्ण परिपत्र व अधिसूचनाओं व राजस्व समाचारों को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है।

प्रदेश में रेबीज उन्मूलन हेतु स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

4 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान की अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह ने शासन सचिवालय में प्रदेश में वर्ष 2030 तक रेबीज उन्मूलन के लिये स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- शुभ्रा सिंह ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सर्वे के अनुसार देश में प्रतिवर्ष लगभग 20 हज़ार लोगों की रेबीज से मृत्यु हो जाती है। इनमें 91.5 प्रतिशत कुत्तों के काटने से होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, नगर निगम एवं तकनीकी पार्टनर संस्थान पाथ के सहयोग से स्टेट एक्शन प्लान तैयार किया है।
- इस प्लान के अनुसार राज्य, ज़िला एवं स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों की अध्यक्षता में विभिन्न सहयोगी विभागों की समन्वय समिति गठित होगी और रेबीज रोग के कारणों पर नियंत्रण व जनजागरूकता के लिये विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी तथा चरणबद्ध तरीके से रेबीज उन्मूलन किया जाएगा।

नोट :

- अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि प्रथम चरण (वर्ष 2023-25) में सामाजिक जागरूकता, डाटा कलेक्शन, कॉल सेंटर की स्थापना, पैरामेडिकल एवं पैरावेटेनरीज को प्रशिक्षित करना, ज़िला स्तर पर एक्शन प्लान बनाना, वैक्सीन की उपलब्धता एवं श्वानों का टीकाकरण किया जाएगा।
- द्वितीय चरण (वर्ष 2025-27) में रेबीज की जाँच के लिये सर्विलांस सिस्टम को मज़बूत करना, पालतू जानवरों का पंजीकरण, जिन जानवरों से रेबीज होता है, उनकी गणना एवं रेबीज मुक्त ज़ोन बनाए जाएंगे।
- अंतिम चरण (वर्ष 2028-30) में प्रथम एवं द्वितीय चरण में की गई गतिविधियों को सुचारु रूप से निरंतर करते हुए संबंधित ज़िलों को रेबीज मुक्त घोषित किया जाएगा।

प्रदेश को मिले 100 नए फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल

चर्चा में क्यों ?

5 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में निरंतर कार्य करने के क्रम में मुख्यमंत्री आवास से 100 फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल (एफआरवी) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रमुख बिंदु

- ये वाहन विभिन्न ज़िलों के पुलिस बेड़े में शामिल किये जाएंगें।
- इन सभी वाहनों को आधुनिक मोबाईल डाटा टर्मिनल (एमडीटी), कैमरा, एनवीआर, वायरलेस सेट, जीपीएस पब्लिक एड्रेस सिस्टम, फर्स्ट एड बॉक्स, स्ट्रेचर, हेलमेट एवं अन्य आपातकालीन उपकरणों से युक्त किया गया है।
- उक्त वाहन कमांड कंट्रोल सेंटर्स में ईआरएस डायल 112 से जुड़े रहेंगे तथा इनकी वास्तविक लोकेशन को ट्रैक भी किया जा सकेगा।
- आमजन द्वारा आपातकालीन स्थिति में डायल 112 पर की गई सभी कॉल्स नज़दीकी एफआरवी को भेजी जाएगी, जिससे उन्हें त्वरित सहायता मिलेगी और अपराधों की बेहतर रोकथाम भी सुनिश्चित हो सकेगी।

नोट :

'e-Journey of Chief Minister's Office, Rajasthan' एवं 'Quotes Shri Ashok Gehlot' पुस्तक प्रसारित

चर्चा में क्यों ?

4 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा तैयार पुस्तक 'e-Journey of Chief Minister's Office, Rajasthan' एवं 'Quotes Shri Ashok Gehlot' प्रसारित की गई है, जिसमें आईटी क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी तस्वीरों के साथ दर्शाई गई है।

प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही विभाग द्वारा लॉन्च की गई विभिन्न योजनाओं एवं प्रमुख संस्थानों के बारे में भी जानकारी साझा की गई है।
- 'Quotes Shri Ashok Gehlot' पुस्तक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विज़न को 'Quotes' के रूप में संकलित किया गया है।
- साथ ही, भारतीय संविधान, लोकतंत्र, युवा, महिला सशक्तीकरण, आईटी, किसान, दलित, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, मानवता, कला एवं संस्कृति के बारे में भी मुख्यमंत्री के विचारों को संकलित किया गया है।

प्रधानमंत्री ने जोधपुर में लगभग 5000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी

चर्चा में क्यों ?

5 अक्तूबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जोधपुर में सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों में लगभग 5000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इन परियोजनाओं में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर में 350 बिस्तरों वाला 'ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक'और पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत विकसित किये जाने वाले सात क्रिटिकल केयर ब्लॉक शामिल हैं।
- एम्स जोधपुर में 'ट्रॉमा, इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर'के लिये एकीकृत केंद्र 350 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा। इसमें ट्राइएज, डायग्नोस्टिक्स, डेकेयर वार्ड, निजी कमरे, मॉड्यूलर ऑपरेटिंग थिएटर, आईसीयू और डायलिसिस कक्ष जैसी विभिन्न सुविधाएँ शामिल होंगी।
- यह रोगियों को बहु-विषयक और व्यापक देखभाल प्रदान करके ट्रॉमा और आपातकालीन मामलों के प्रबंधन में एक समग्र दृष्टिकोण लाएगा।
- प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक नए टर्मिनल भवन के विकास की आधारशिला भी रखी। कुल 480 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नई टर्मिनल बिल्डिंग लगभग 24,000 वर्गमीटर क्षेत्र में विकसित की जाएगी और व्यस्त समय के दौरान 2,500 यात्रियों को सेवाएँ प्रदान करने के लिये सुसज्जित होगी।
- यह सालाना 35 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने के साथ-साथ कनेक्टिविटी में सुधार करेगी और इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- प्रधानमंत्री ने आईआईटी जोधपुर परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। यह अत्याधुनिक परिसर 1135 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है, जो अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार पहलों का समर्थन करने के लिये उच्च गुणवत्ता वाली समग्र शिक्षा प्रदान करने और बुनियादी ढाँचे के निर्माण की दिशा में एक कदम है।
- राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में बुनियादी ढाँचे के उन्नयन के लिये, प्रधान मंत्री ने 'केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला', स्टाफ क्वार्टर और 'योग और खेल विज्ञान भवन'राष्ट्र को समर्पित किया।
- वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय, 600 छात्रों की क्षमता वाले छात्रावास और छात्रों के लिये भोजन कक्ष सुविधा की आधारशिला रखी।
- राजस्थान में सड़क बुनियादी ढाँचे में सुधार लाने वाले कदम के तहत, प्रधानमंत्री ने एनएच-125ए पर जोधपुर रिंग रोड के कारवाड़ से डांगियावास खंड को चार लेन बनाने सहित कई सड़क विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी; जालोर (एनएच-325) के रास्ते बालोतरा से सांडेराव खंड के प्रमुख शहरी भागों के सात बाईपास का निर्माण; एनएच-25 के पचपदरा-बागुंडी खंड को चार लेन बनाने की परियोजना समेत विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया।
- ये सड़क परियोजनाएँ लगभग 1475 करोड़ रुपए की संचयी लागत से बनाई जाएंगी। जोधपुर रिंग रोड शहर में यातायात के दबाव को कम करने और वाहन प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा।
- यह सभी परियोजनाएँ क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार और व्यापार को बढ़ावा देने के साथ-साथ रोज़गार सृजन करेंगी और आर्थिक विकास में मदद करेंगी।
- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राजस्थान में दो नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। इनमें जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली एक नई ट्रेन - रुणिचा एक्सप्रेस और मारवाड़ जंक्शन को खंबली घाट से जोड़ने वाली एक नई हेरिटेज ट्रेन शामिल है।
- रुणिचा एक्सप्रेस जोधपुर, डेगाना, कुचामन सिटी, फुलेरा, रींगस, श्रीमाधोपुर, नीम का थाना, नारनौल, अटेली, रेवाड़ी से होकर गुज़रेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी के साथ सभी शहरों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
- मारवाड़ जं.-खांबली घाट को जोड़ने वाली नई हेरिटेज ट्रेन पर्यटन को बढ़ावा देगी और क्षेत्र में रोजगार पैदा करेगी।

प्रदेश में होगा 'राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम'

चर्चा में क्यों ?

8 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 'नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम' की तर्ज़ पर प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के लिये 'राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम' का आयोजन होगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इसमें चयनित 10 हज़ार विद्यार्थियों को कक्षा 11 व 12 में प्रतिमाह 1250 और स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिये प्रतिमाह 2000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की है।
- इस परीक्षा के लिये कक्षा 10वीं में पहली बार प्रविष्ठ हो रहे विद्यार्थी पात्र होंगे। परीक्षा हिन्दी व अंग्रेज़ी माध्यम में होगी। परीक्षा के लिये नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को बनाया गया है।
- परीक्षा में दो प्रश्न-पत्र होंगे। पहला, मानसिक योग्यता परीक्षा और दूसरा, शैक्षिक योग्यता परीक्षा का होगा। इसमें विद्यार्थी नि:शुल्क आवेदन कर सकेंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

संक्रामक रोग संस्थान जोधपुर का होगा उन्नयन

चर्चा में क्यों ?

8 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर स्थित संक्रामक रोग संस्थान को उच्चस्तरीय अनुसंधान केंद्र में विकसित करने के द्वितीय फेज में विभिन्न विकास कार्यों के लिये 3 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

विदित है कि प्रदेश सरकार राज्य में चिकित्सा सुविधाओं का निरंतर विकास कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने जोधपुर के संक्रामक रोग संस्थान के उन्नयन के लिये वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

प्रस्ताव के अनुसार, 3 करोड़ रुपए की लागत से संस्थान में प्रशासनिक खंड, नवीन सेंट्रल ड्रग स्टोर, पीडियाट्रिक क्यूबीकल हेतु सेंट्रल ऑक्सीजन पाईप लाईन तथा लिफ्ट का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही, संस्थान में पी.पी.पी. मोड पर 128 स्लाइस सी.टी. मशीन भी स्थापित की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में इस केंद्र को उच्चस्तरीय अनुसंधान केंद्र में विकसित करने की घोषणा की गई थी, जिसकी क्रियान्विति में उक्त स्वीकृति प्रदान की गई है।

नोट :

राज्य में 7 बृहद् जलापूर्ति परियोजनाओं के लिये 21 हज़ार 613 करोड़ रुपए स्वीकृत

चर्चा में क्यों ?

8 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 7 बृहद् जलापूर्ति परियोजनाओं के लिये 21 हज़ार 613 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश सरकार राज्य में अंतिम व्यक्ति को पेयजल उपलब्ध करवाने एवं जल सुरक्षा से युक्त भविष्य का निर्माण करने के लिये महत्त्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 बृहद् जलापूर्ति परियोजनाओं के लिये वित्तीय प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।
- प्रस्ताव के अनुसार, इन 7 पेयजल परियोजनाओं के द्वारा प्रदेश के 4,63,580 घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन दिये जा सकेंगे।
- 'कालीतीर परियोजना'के अंतर्गत 709.41 करोड़ रुपए की लागत से धौलपुर एवं भरतपुर ज़िलों के 470 गाँवों में चंबल नदी का पानी पहुँचाकर पेयजल कनेक्शन दिये जा सकेंगे। साथ ही, अलवर एवं भरतपुर ज़िलों के 1,237 गाँवों को 5374.15 करोड़ रुपए की लागत से बृहद् पेयजल परियोजना के तहत चंबल नदी के पानी के द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी।
- इसके अतिरिक्त 3990.08 करोड़ रुपए की लागत से करौली एवं सवाई माधोपुर ज़िलों के 1,426 गाँवों को बृहद् पेयजल परियोजना के तहत चंबल नदी के पानी से पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी।
- जाखम बांध के द्वारा चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद एवं उदयपुर ज़िलों के 1,473 गाँवों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिये 3529.90 करोड़ रुपए का प्रावधान भी प्रस्ताव में किया गया है।
- इसके अलावा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल द्वारा फलौदी ज़िले के लोहावट एवं देंचू के 79 गाँवों एवं 325 ढाणियों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये 229.73 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्ताव में किया गया है।
- सीकर एवं झुंझुनूं ज़िलों के इंदिरा गांधी नहर परियोजना से अब तक नहीं जुड़े गाँवों को बृहद् जल परियोजना द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये 7583.15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत 'जायल मातासुख परियोजना'में नागौर ज़िले के 123 गाँवों एवं 244 ढाणियों को पेयजल कनेक्शन देने के लिये 196.68 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
- इन बृहद् जलापूर्ति परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं वित्त पोषण राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज निगम द्वारा किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से प्रदेश के बृहद् भाग में आमजन को सुगमता से पेयजल उपलब्ध हो पाएगा। इससे भौगोलिक परिस्थितियों एवं अन्य कारणों के कारण पेयजल आपूर्ति की समस्याओं से ग्रसित क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी एवं अन्य समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकेगा।

राजस्थान घटनाक्रम

चर्चा में क्यों ?

8 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विविध श्रेणी के 510 विद्यालयों को राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय में रूपांतरित करने एवं 47 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्वीकृति से प्राथमिक स्तर के 44, उच्च प्राथमिक स्तर के 294, माध्यमिक स्तर के 13 एवं उच्च माध्यमिक स्तर के 172 विद्यालयों को राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय में रूपांतरित किया जाएगा। इससे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को अंग्रेज़ी माध्यम में शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में एक-एक हज़ार राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय खोले जाने की घोषणा की थी। पूर्व में 709 विद्यालयों के लिये स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

नोट :

- इसी प्रकार, मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप 47 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 72 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय/विषय खोलने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी है।
- प्रस्ताव के अनुसार 41 विद्यालयों में विज्ञान, 8 विद्यालयों में कला, 4 विद्यालयों में वाणिज्य संकाय तथा 19 विद्यालयों में कृषि विषय शुरू किये जाएंगे। साथ ही, नवीन संकायों/विषयों के संचालन हेतु व्याख्याता स्कूल शिक्षा के 41 एवं प्रयोगशाला सहायक के 11 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है।

नोट :

राज-सिलिकोसिस पोर्टल में AI आधारित चेस्ट x-ray ऐप्लीकेशन का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

6 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि सिलिकोसिस पहचान एवं सिलिकोसिस प्रमाणीकरण प्रक्रिया को अधिक सुगम, सरल एवं तकनीकी आधारित बनाने के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI Tools/ Application विकसित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. समित शर्मा ने बताया कि राज सिलिकोसिस पोर्टल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित Application विकसित की गई है, जिसे नवीन सिलिकोसिस पोर्टल पर सिलिकोसिस प्रमाणीकरण प्रक्रिया में रेडियोलॉजिस्ट स्तर/ M.O. (Medical Officer) स्तर तथा ज़िला न्यूमोकोनियोसिस बोर्ड के स्तर पर उपयोग करने हेतु क्रियाशील कर दिया गया है।
- इसका उद्घाटन अभी हाल ही में, राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली द्वारा किया गया है।
- AI आधारित ऐप्लीकेशन के फायदे
  - एआई-सक्षम सिलिकोसिस स्क्रीनिंग सिस्टम समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों को चिकित्सकीय सेवा और आर्थिक सहयोग प्रदान करने में तेज़ी लाने के लिये प्रौद्योगिकी के उपयोग पर सरकार के प्रगतिशील रुख का एक प्रमाण है।
  - यह ऐप्लीकेशन चेस्ट x-ray को deep learning के आधार पर तय किये गए मानकों पर जाँच करता है। इससे फील्ड में कार्यरत् रेडियोलॉजिस्ट को चेस्ट x-ray के माध्यम से सिलिकोसिस पीड़ित को पहचानने में सहायता मिलेगी तथा यह मानवीय त्रुटियों को कम करने में सहायक होगा।
  - इस तकनीक के माध्यम से रेडियोलॉजिस्ट के कार्यभार में कमी होगी तथा प्राप्त आवेदनों में से जो लोग सिलिकोसिस से पीड़ित नहीं हैं, उनकी छँटनी करने में आसानी होगी।
  - त्वरित स्क्रीनिंग से शीघ्र चिकित्सा सहायता मिल सकेगी और स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों पर बोझ कम हो सकेगा।
  - बीमारी का शीघ्र पता लगने से समय पर हस्तक्षेप और उपचार की अनुमति मिल सकेगी, जिससे संभावित रूप से रोग की प्रगति को रोका जा सकेगा।

नोट :

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है ?
  - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है- बनावटी (कृत्रिम) तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता।
  - इसके ज़रिये कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है, जिनके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है।
- AI आधारित ऐप्लीकेशन किस प्रकार कार्य करेगा ?
  - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन एक स्क्रीनिंग टूल है, जो तकनीक का उपयोग कर चेस्ट एक्स-रे की Findings का विश्लेषण कर सुझाव देगा कि जिस व्यक्ति का चेस्ट एक्स-रे है, उसे सिलिकोसिस की संभावना है अथवा नहीं तथा इस प्रकार यह AI Based Application रेडियोलॉजिस्ट के लिये सिलिकोसिस प्रमाणीकरण में निर्णय लेने में सहायता करेगा।
  - इस पहल का मूल एक उन्नत deep learning मॉडल है, जिसमें व्यापक डाटासेट का उपयोग करके हर चरण में सावधानीपूर्वक विकसित और कठोरता से परीक्षण किया गया है। इस हेतु राज्य भर से प्राप्त 40 हज़ार चेस्ट एक्स-रे छवियों का उपयोग किया गया है। इस प्रयास को वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीकी विशेषज्ञता द्वारा समर्थित किया गया है।
  - रेडियोलॉजिस्ट एवं सिलिकोसिस प्रमाण-पत्र जारीकर्त्ता अधिकारी अपने चिकित्सकीय विवेक (Clinical Judgment) अनुसार प्रमाणीकरण हेतु पूर्व के समान निर्णय कर सकेंगे।
- राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस पॉलिसी-2019
  - राज्य सरकार द्वारा न्यूमोकोनियोसिस पॉलिसी राजस्थान-2019 लागू की गई थी। बीओसीडब्ल्यू सहित खनन श्रमिकों के कल्याण के लिये सिलिकोसिस नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।
  - इस नीति में सिलिकोसिस ग्रस्त रोगियों को 3 लाख की सहायता राशि के अलावा 1.5 हज़ार रुपए प्रतिमाह की पेंशन सहित अन्य परिलाभों का प्रावधान है।
  - उक्त हेतु निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा राज सिलिकोसिस पोर्टल के माध्यम से सिलिकोसिस प्रमाणीकरण एवं भुगतान का कार्य किया जाता है।
  - इस प्रक्रिया में लाभार्थी द्वारा आवेदन पश्चात् रेडियोलॉजिस्ट द्वारा चेस्ट X-Ray के विश्लेषण व जाँच पश्चात् सिलिकोसिस से पीड़ित होने के बारे में प्रमाणीकरण किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने 8 बोर्ड के गठन को दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

7 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 8 विभिन्न बोर्ड के गठन को स्वीकृति दी है।

प्रमुख बिंदु

- इन नवगठित बोर्ड में राजस्थान राज्य राजा बली कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य मेघवाल कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य पुजारी कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य केवट कल्याण (माँ पूरी बाई कीर) बोर्ड, राजस्थान राज्य जाटव कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य धाणका कल्याण बोर्ड एवं राजस्थान राज्य चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड शामिल हैं।
- ये सभी बोर्ड संबंधित वर्गों की स्थिति का जायजा लेने, प्रामाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर वर्गों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा इनके पिछड़ेपन को दूर करने के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देंगे।
- ये बोर्ड संबंधित वर्ग के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएँ प्रस्तावित करने, उनके लिये वर्तमान में संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में विभिन्न विभागों से समन्वय करने, परंपरागत व्यवसाय को वर्तमान तौर-तरीकों से आगे बढ़ाने, रोज़गार को बढ़ावा देने तथा शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नयन के संबंध में सुझाव देंगे। साथ ही, सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों के विरुद्ध ठोस उपाय करने सहित अन्य सुझाव भी राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

नोट :

- इन सभी बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं तीन सदस्य सहित 5-5 गैर-सरकारी सदस्य होंगे तथा राज्य के विभिन्न विभागों के शासन सचिव, आयुक्त, निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक स्तर के अधिकारी सरकारी सदस्य होंगे।
- इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड या राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक स्तर के अधिकारी अथवा उनका प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

राजस्थान में होगा जाति आधारित सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों ?

7 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार अपने संसाधनों से प्रदेश में जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी। सर्वेक्षण में राज्य के समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर के संबंध में जानकारी एवं आँकड़े एकत्रित किये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय की अनुपालना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा इनका विशेष अध्ययन कराकर वर्गों के पिछड़ेपन की स्थिति में सुधार लाने के लिये विशेष कल्याणकारी उपाय और योजनाएँ लागू की जाएंगी। इससे सभी वर्गों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
- सर्वेक्षण कार्य आयोजना (आर्थिक एवं सांख्यिकी) विभाग द्वारा नोडल विभाग के रूप में संपादित किया जाएगा। साथ ही, सभी ज़िला कलेक्टर सर्वेक्षण के लिये नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ग्राम एवं पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्मिकों की सेवाएँ ले सकेंगे।
- इस कार्य के लिये नोडल विभाग द्वारा प्रश्नावली तैयार की जाएगी। इसमें उन समस्त विषयों का उल्लेख होगा, जिनसे प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
- सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाएँ एवं आँकड़े ऑनलाइन फीड किये जाएंगे। इसके लिये सूचना-प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा पृथक् से विशेष सॉफ्टवेयर एवं मोबाइल ऐप बनाया जाएगा। सर्वेक्षण से प्राप्त संकलित की गई सूचनाएँ विभाग सुरक्षित रखेगा।

राज्य में विधानसभा चुनाव-2023 का कार्यक्रम घोषित

चर्चा में क्यों ?

9 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने शासन सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में विधानसभा चुनाव-2023 की घोषणा कर दी गई है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश की सभी दो सौ सीटों के लिये आगामी 23 नवंबर, 2023 को मतदान होगा तथा 3 दिसंबर को मतगणना होगी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य में कुल 5 करोड़ 27 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
- आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रदेश में स्थानांतरण एवं नियुक्तियों पर रोक लग गई है। अति आवश्यक होने पर राज्य सरकार निर्वाचन आयोग से मंज़ूरी लेने के बाद ही चुनाव से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थानांतरित कर सकेगी।
- प्रदेश की सभी दो सौ सीटों के लिये चुनाव प्रक्रिया के तहत 30 अक्तूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। राज्य में 6 नवंबर तक नामांकन दाखिल किये जा सकेंगे। 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 9 नवंबर तक नाम वापस लिये जा सकेंगे। 23 नवंबर को मतदान होगा तथा 3 दिसंबर को मतगणना होगी।

नोट :

- मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में 34 अनुसूचित जाति, 25 अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित हैं, वहीं 141 सीटें सामान्य वर्ग के लिये हैं।
- उन्होंने बताया कि सरकारी वाहनों, हेलीकॉप्टर एवं विमान के चुनाव कार्यों में उपयोग पर भी रोक रहेगी। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकाशन सामग्री यथा पोस्टर, पैंफलेट आदि पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम आवश्यक रूप से प्रकाशित करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत कार्यवाही की जाएगी।
- मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के अनुसार राज्य में कुल 5 करोड़ 27 लाख से अधिक मतदाता हैं। इसमें 2 करोड़ 75 लाख से अधिक पुरुष और 2 करोड़ 51 लाख से अधिक महिला मतदाता हैं। 1 लाख 41 हज़ार 898 सर्विस मतदाता भी हैं।
- प्रदेश में कुल 51 हज़ार 756 मतदान केंद्र हैं, जिनमें 10 हज़ार 415 शहरी तथा 41 हज़ार 341 ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। 18 से 19 वर्ष की आयु के लगभग 22 लाख युवा मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
- गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिये प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की गई है। इन चुनावों में 18.05 लाख से अधिक मतदाताओं को विकल्प के तौर पर ये सुविधा मिल सकेगी।
- आयोग के निर्देशानुसार महत्त्वपूर्ण मतदान केंद्रों और संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित सभी मतदान केंद्रों में अथवा सहायक मतदान केंद्रों सहित कुल मतदान केंद्रों के 50 फीसदी से ज़्यादा 26 हज़ार मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी।
- आयोग ने व्यापक सहभागिता और पारदर्शिता लाने के लिये आईटी एप्लीकेशन का उपयोग बढ़ाया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की सी-विजिल ऐप के ज़रिये शिकायत की जा सकती है। केवाईसी ऐप के ज़रिये उम्मीदवार के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह वोटर हैल्प लाइन ऐप, सक्षम ऐप और सुविधा पोर्टल के ज़रिये भी घर बैठे संबंधित सूचनाएँ और सुविधाएँ प्राप्त की जा सकती हैं।
- लैंगिक समानता और निर्वाचन प्रक्रिया में महिलाओं की रचनात्मक भागीदारी को बढ़ाने के लिये प्रदेश में महिलाओं द्वारा संचालित कुल 1600 मतदान केंद्र, दिव्यांगजन द्वारा कुल 200, युवाओं द्वारा संचालित कुल 1600 एवं आदर्श मतदान केंद्र 1600 स्थापित किये जाएंगे।
- प्रदेश में पहली बार PVTG श्रेणी के अंतर्गत शामिल सहरिया जनजाति के समस्त पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल किये जा चुके हैं। इस श्रेणी में प्रदेश में कुल 77 हज़ार 343 मतदाता हैं।

प्रदेश में पहली बार अनिवार्य सेवाओं की कैटेगरी में मीडियाकर्मी शामिल

चर्चा में क्यों ?

11 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2023 में सर्विस वोटर्स के अलावा अन्य आठ विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र के ज़रिये वोटिंग की सुविधा दी है। इस श्रेणी में पहली बार राजस्थान में मीडियाकर्मियों को भी शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है। बिजली-पानी, रोडवेज-मेट्रो, डेयरी, फायर फाइटर, चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं।
- निर्वाचन आयोग से जारी आदेशों के मुताबिक मेडिकल सेक्टर में डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मचारी, ऊर्जा विभाग में इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन, पीएचईडी में पंप ऑपरेटर, टर्नर, राजस्थान की दुग्ध समितियों में काम करने वाले कर्मचारी, रोडवेज में ड्राइवर-कंडक्टर और निर्वाचन आयोग से अधिकृत मीडिया कर्मचारियों को इस साल से पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्र) के ज़रिये वोटिंग की सुविधा दी जाएगी।
- सर्विस वोटर्स की श्रेणी में पहली बार पत्रकारों को शामिल किया गया है। अभी तक सर्विस वोटिंग की सुविधा चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों-अधिकारियों, सेना या पैरा मिलिट्री से जुड़े जवानों को ही मिलती थी।

नोट :

- इन सभी अनिवार्य सर्विस वालों को अब से पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है। संबंधित विभाग बताएंगे कि उनके यहाँ कितने ऐसे कर्मचारी हैं, जिनकी वोटिंग के दिन ड्यूटी रहेगी और वो उस दिन वोट देने से वंचित रह सकते हैं। उस सूची के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी उन कर्मचारियों को फार्म 12-डी जारी करेगा और उनको बैलेट पेपर के ज़रिये वोटिंग की सुविधा फैसिलिटेशन सेंटर पर दी जाएगी।

राजस्थान में पहली बार पात्र मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा

चर्चा में क्यों ?

12 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आयोग द्वारा राजस्थान में पहली बार पात्र मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार, राजस्थान में वर्ष 2023 के विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की सुविधा पात्र 18.05 लाख मतदाताओं को विकल्प के तौर पर मिल सकेगी। इसके अंतर्गत बूथलेवल अधिकारी घर-घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के बारे में जानकारी देंगे।

नोट :

- यह सुविधा 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं को मिलेगी।
- यह सुविधा विकल्प के रूप में है। योग्य मतदाता यदि इस सुविधा का चयन करना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिवस के भीतर 12-डी फॉर्म भरना होगा और इसे भरकर बीएलओ को जमा कराना होगा।
- होम वोटिंग का चयन करने वाले मतदाताओं की सूची निर्वाचक अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी।
- गठित मतदान दल इन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के ज़रिये मतदान करवाएगा।
- विदित हो कि प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 11,76,085 मतदाता एवं विशेष योग्यजन के रूप में 5,60,876 मतदाता पंजीकृत हैं।

प्रदेश में जुनोटिक डिजीज कंट्रोल हेतु बनेगा 'स्टेट वन-हेल्थ एक्शन प्लान'

चर्चा में क्यों ?

13 अक्तूबर, 2023 को प्रदेश की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने जयपुर में आयोजित मल्टी सेक्टरल कंसल्टेशन वर्कशॉप के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जुनोटिक संक्रमण वाली बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिये 'स्टेट वन-हेल्थ एक्शन प्लान' बनाकर कार्यवाही की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) एवं यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एवं प्रिवेंशन संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में राष्ट्रीय स्तर के विषय-विशेषज्ञ एवं तकनीकी पार्टनर संस्थानों के प्रतिनिधिगण पारस्परिक विचार मंथन कर देश में पहले राजस्थान स्टेट वन-हेल्थ एक्शन प्लान की रूपरेखा तैयार करेंगे।
- कार्यशाला में बताया गया कि मानव में 60 प्रतिशत बीमारियों के संक्रमण के कारण प्राकृतिक व जुनोटिक होते हैं, जैसे- वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स व अन्य से संक्रमण फैलता है।
- विभिन्न निकायों, कार्यक्षेत्र के विचार-विमर्श, उनके अनुभव एवं प्राकृतिक स्थितियों के आधार पर वन-हेल्थ एक्शन प्लान लागू कर जुनोटिक डिजीज पर नियंत्रण करने की कार्यवाही की जाएगी।
- शुभ्रा सिंह ने बताया कि कोविड जैसी महामारियों का सामना करने के लिये आधारभूत संसाधन व प्राथमिक प्रबंधन की पूर्व तैयारी करनी आवश्यक है और इसी को ध्यान में रखकर राजस्थान में रेबीज उन्मूलन के लिये स्टेट एक्शन प्लान लागू कर कार्यवाही की जा रही है।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि जुनोटिक डिजीज कंट्रोल हेतु तैयार किये जाने वाले वन-हेल्थ एक्शन प्लान में शामिल होने वाली गतिविधियों में से अनेक गतिविधियों के लिये पहले से तैयारी की जा चुकी है। प्रभावी क्रियान्वयन के लिये राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एनसीडी एवं सीडीसी जैसे संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा।

नोट :

राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर मिला 'टोबेको कंट्रोल एक्सीलेंस अवॉर्ड'

चर्चा में क्यों ?

20 अक्तूबर, 2023 को दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में तंबाकू नियंत्रण एवं रोकथाम की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिये राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर 'टोबेको कंट्रोल एक्सीलेंस अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान की अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हेकाली जिमोमी एवं एडिशनल डीडीजी डॉ. एल स्वास्थिचरण ने राजस्थान में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में हुए नवाचारों एवं कोटपा एक्ट के बेहतरीन क्रियान्वयन हेतु राजस्थान को टोबेको कंट्रोल एक्सीलेंस अवॉर्ड प्रदान किया है।
- स्टेट नोडल ऑफिसर, एनटीसीपी डॉ. एसएन धौलपुरिया एवं एडिशनल एसपीओ श्री नरेंद्र सिंह ने यह अवार्ड प्राप्त किया।
- प्रदेश में तंबाकू फ्री यूथ कैम्पेन के माध्यम से युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। इसके तहत 60 दिवसीय तंबाकू मुक्त राजस्थान कार्ययोजना लागू कर जागरूकता कार्यक्रम, शपथ ग्रहण सहित विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की गई।
- उल्लेखनीय है कि राजस्थान टोबेको फ्री यूथ कैम्पेन 2023 की सभी गतिविधियों में अव्वल रहा है। टोबेको फ्री यूथ कैम्पेन-2023 में कोटपा एक्ट के तहत सेक्शन 4 एवं सेक्शन 6 के तहत सर्वाधिक चालान राजस्थान में किये गए। इसी प्रकार अभियान के तहत आईईसी गतिविधियों, तंबाकू मुक्त गाँवों, तंबाकू मुक्त शैक्षणिक परिसरों आदि गतिविधियों में भी राजस्थान अव्वल रहा है।

नोट :

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लॉन्च किया 'सहज भीलवाड़ा' ऐप

चर्चा में क्यों ?

23 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता द्वारा भीलवाड़ा ज़िला निर्वाचन अधिकारी के नवाचार के रूप में विकसित किये गए 'सहज भीलवाड़ा'ऐप को वर्चुअली लॉन्च किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस ऐप के माध्यम से 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के साथ मतदान प्रक्रिया के पर्यवेक्षण को सुगम बनाया जाएगा।
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने ऐप लॉन्च के दौरान कहा कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा वरिष्ठ नागरिकजन, विशेष योग्यजन, कोविड प्रभावित मतदाताओं का राजस्थान विधानसभा आमचुनाव 2023 में अधिकाधिक मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उक्त श्रेणी के अनुपस्थित मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जा रही है।
- उन्होंने भीलवाड़ा ज़िले में होम वोटिंग संबंधित समस्त प्रक्रिया की निगरानी एवं प्रभावी पर्यवेक्षण के लिये विकसित किये गए आईटी आधारित 'सहज भीलवाड़ा'ऐप के संबंध में कहा कि इस ऐप के माध्यम से राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 में वरिष्ठ नागरिक व विशेष योग्यजन श्रेणियों के अनुपस्थित मतदाताओं की शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- यह ऐप समस्त बीएलओ, पीओ, आरओ इत्यादि निर्वाचन से संबंधी कार्मिकों व अधिकारियों को अपने दायित्वों के सफल निष्पादन में सहायक सिद्ध होगा।
- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव प्रक्रिया को सुगम व सरल बनाने के लिये ज़िले के 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिये प्रदेश में विधानसभा आम चुनावों में पहली बार होम वोटिंग की पहल की गई है।
- इन चुनावों में पात्र मतदाताओं को मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने के विकल्प के तौर पर यह सुविधा मिलेगी। भीलवाड़ा ज़िले में नवाचार के तहत इस ऐप के माध्यम से 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के साथ मतदान प्रक्रिया के पर्यवेक्षण को सुगम बनाया जाएगा।
- विधानसभा आम चुनाव के दौरान प्रपत्र 12 घ के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया के पर्यवेक्षण को सुगम व सरल बनाने के लिये भीलवाड़ा ज़िले में 'सहज भीलवाड़ा'ऐप नवाचार के रूप में लॉन्च किया गया है।
- 'सहज भीलवाड़ा'ऐप की विशेषताएँ-
  - सहज भीलवाड़ा ऐप एवीएससी और एवीपीडी मतदाताओं के लिये 'होम वोटिंग'की बेहतर निगरानी में मदद करने के लिये विकसित एक आईटी एप्लिकेशन है।
  - रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म 12 घ भरने, मतदान की वास्तविक समय निगरानी में करेगा मदद।
  - अनुपस्थित मतदाताओं के लिये मतदान की पूरी प्रक्रिया में शामिल रिटर्निंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर तथा बूथ लेवल ऑफिसर के लिये तीन अलग-अलग लॉगिन प्रदान किये गए हैं।
  - यह एप्लीकेशन रिटर्निंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर तथा बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा अपने स्तर पर पहले से की जा रही प्रक्रिया को प्रतिस्थापित नहीं करेगा, बल्कि संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी में रिटर्निंग ऑफिसर को सुविधा प्रदान करेगा।
  - यह एप्लीकेशन रिटर्निंग अधिकारी को बेहतर कार्ययोजना बनाने में मदद करेगा एवं इससे मतदान दलों का शेड्यूल और तैनाती भी आसान हो जाएगी।
  - ऐप में पात्र 80+ बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं को एसएमएस के माध्यम से मतदान की तारीख और समय के बारे में सूचित करने की सुविधा भी शामिल है। इससे मतदाता को जानकारी रहेगी कि मतदान प्रक्रिया के लिये पोलिंग पार्टी उनके घर कब आएगी।
  - बीएलओ लॉगिन के स्तर पर फॉर्म 12 घ विवरण प्रविष्टि, भरे हुए फॉर्म 12घ के साथ मतदाता की तस्वीर, बेंचमार्क विकलांगता प्रमाण-पत्र, जीपीएस लोकेशन आदि जैसी सुविधाएँ एप्लीकेशन में सम्मिलित की गई हैं।

नोट :

- पीओ लॉगिन के स्तर पर मतदान दल कर्मी संबंधित अनुपस्थित मतदाता के घर तक पहुँचने के लिये ऐप में दिये गए जीपीएस लोकेशन सुविधा का उपयोग कर मतदाता के घर पहुँच सकते हैं और सहज ऐप पर मतदान की स्थिति को अपडेट कर सकते हैं।

राजस्थान पत्रिका के अरुण, मुंडियार व पारीक को मिला 'लाडली मीडिया अवॉर्ड'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिष्ठित संस्था 'पॉपुलेशन फर्स्ट' द्वारा राजस्थान पत्रिका जयपुर के सीनियर न्यूज एडिटर अरुण कुमार, राजस्थान पत्रिका भीलवाड़ा के संपादकीय प्रभारी कानाराम मुंडियार व पत्रिका रतलाम के संपादकीय प्रभारी सिकंदर पारीक को 'लाडली मीडिया अवॉर्ड्स 2023' से सम्मानित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि 'पॉपुलेशन फर्स्ट'संस्था की ओर से लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिये 'लाडली मीडिया अवॉर्ड'दिया जाता है। संस्था द्वारा 'लाडली मीडिया अवॉर्ड'की घोषणा इस साल 21 अक्तूबर को की गई थी।
- इस अवार्ड के लिये देश भर से 13 भाषाओं के करीब 850 से ज्यादा पत्रकारों ने प्रविष्टियाँ भेजी थी, जिनमें जूरी मेंबर्स ने 87 का चयन किया और उन्हें सम्मानित किया। इनके अलावा 31 पत्रकारों को जूरी प्रशंसा पत्र दिया गया।
- राजस्थान पत्रिका जयपुर के सीनियर न्यूज एडिटर अरुण कुमार को जेंडर सेंस्टिविटी श्रेणी में '40 हजार करोड़ की बेगारी'शीर्षक से प्रकाशित स्टोरी के लिये, राजस्थान पत्रिका भीलवाड़ा के संपादकीय प्रभारी कानाराम मुंडियार को 'फूलिया कला की बेटियों का कमाल, हर साल हॉकी में छू रही आसमान'शीर्षक से प्रकाशित स्टोरी के लिये व पत्रिका रतलाम के संपादकीय प्रभारी सिकंदर पारीक को बालिका शिक्षा से जुड़े कॉलम 'तालीम से तरक्की'के लिये यह अवॉर्ड दिया गया।
- जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित समारोह में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर के कुलपति प्रो. डॉ. देव स्वरूप, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के पॉलिसी व साझेदारी प्रमुख जयदीप बिस्वास, यूएनएफपीए की प्रोग्राम मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट अनुजा गुलाटी और लोक संवाद संस्थान के सचिव कल्याण सिंह कोठारी ने राजीव पांडेय को सम्मानित किया।

नोट :

सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान - 'असुरक्षित स्पर्श'पर जागरूकता का दूसरा चरण 28 अक्तूबर को

चर्चा में क्यों ?

25 अक्तूबर, 2023 को राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि प्रदेश के 65 हज़ार से अधिक सरकारी स्कूलों में 'सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान' (एसएसएसआर-सेफ स्कूल सेफ राजस्थान) अभियान के तहत 'नो बैग डे'पर 28 अक्तूबर को असुरक्षित स्पर्श (गुड टच बैड टच) के बारे में जागरूकता का दूसरा चरण आयोजित होगा।

प्रमुख बिंदु

- शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि इसके तहत एक ही दिन में एक निश्चित समयावधि (प्रात: 8 बजे से 12 बजे के दौरान) में सभी बच्चों को स्कूलों के स्तर पर तैयार किये गए मास्टर ट्रेनर्स विशेष प्रशिक्षण देंगे।
- विशेष रूप से तैयार इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के तहत बच्चों को बैड टच की स्थिति में चिल्लाते हुए 'नो' बोलकर उस स्थान या व्यक्ति से सावधानी के साथ दूर भागने (गो) और इसके बारे में बिना किसी डर या घबराहट के किसी बड़े या जिस पर उनको सबसे ज़्यादा भरोसा हो, को इसके बारे में बताने (टैल) की 'नो-गो-टैल' की थ्योरी सिखाई जाती है।
- मनोवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित अंतराल पर यदि तीन चरणों में बच्चों को इस संवेदनशील विषय पर प्रशिक्षित किया जाए तो ये स्थाई रूप से उनकी समझ और व्यवहार का हिस्सा बन जाता है।
- वे 'असुरक्षित स्पर्श'का सजगता और सतर्कता से सामना करते हुए खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। इसी उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चरणबद्ध रूप से प्रशिक्षणों की रूपरेखा तैयार की गई है। इस माह दूसरे चरण के बाद नए साल में जनवरी माह में प्रशिक्षण का तीसरा चरण आयोजित होगा।
- इस अभियान के पहले चरण में गत 26 अगस्त (शनिवार) को प्रदेश की 65 हज़ार 122 सरकारी स्कूलों में 'नो बैग डे'की गतिविधि के तहत एक लाख से अधिक सेशंस में 58 लाख से अधिक बच्चों को 'असुरक्षित स्पर्श'के बारे में जागरूक और प्रशिक्षित किया गया था।
- शासन सचिव ने बताया कि विभाग की इस अभिनव पहल के तहत राज्य स्तर पर 1200 मास्टर ट्रेनर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इनके माध्यम से जिलों में आयोजित ट्रेनिंग सेशंस में संबंधित ज़िले के सभी स्कूलों से एक शिक्षक को 'मास्टर ट्रेनर'बनाया गया है।
- प्रथम चरण में स्कूलों के स्तर पर तैयार इन 'मास्टर ट्रेनर्स'द्वारा अपने-अपने विद्यालयों में समस्त बच्चों को असुरक्षित स्पर्श (गुड टच बैड टच) की ट्रेनिंग दी गई थी। इसी तर्ज पर 'नो बैग डे'के तहत आगामी 28 अक्तूबर को प्रदेश के 65 हज़ार से अधिक विद्यालयों में दूसरा चरण आयोजित होगा।

नोट :

विभिन्न क्षेत्रों की 10 प्रभावशाली महिलाओं को राज्यपाल ने किया सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

26 अक्तूबर, 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने इंडिया टुडे समूह द्वारा आयोजित इंडिया टुडे वूमेन समिट एंड अवॉर्ड समारोह- शक्ति, साहस और सफलता उत्सव में विभिन्न क्षेत्रों में महती कार्य करने वाली दस प्रभावशाली महिलाओं को 'इंडिया टुडे' अवॉर्ड से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्यपाल ने तारा अहलूवालिया (समाज सेवा क्षेत्र), भारतीय घुड़सवारी एथलीट दिव्यकृति (खेल क्षेत्र), संतोष देवी (खेती क्षेत्र), अनीता पालीवाल (राजसमंद के पिपलांत्री गाँव में 18 वर्षों से नवाचार कर पर्यावरण संरक्षण), प्रीति चंद्रा (उत्कृष्ट प्रशासनिक सेवा), नीरू यादव (ग्रामीण विकास), डॉ. कृति भारती (बाल विवाह रोकथाम के प्रयास हेतु), डॉ. मेवा भारती (श्रमिक महिला अधिकारों हेतु), मोनिका जांगिड़ (दिव्यांग बच्चों के लिये) और अदम्य साहस का परिचय देने के लिये वसुंधरा चौहान को इंडिया टुडे अवॉर्ड से सम्मानित किया।
- उन्होंने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम'की चर्चा करते हुए कहा कि इससे महिलाओं को लोकतंत्र में भागीदारी के अधिकाधिक अवसर मिल सकेंगे। उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही समाज में फैली कुरीतियों के निवारण के लिये भी सभी को मिलकर प्रयास करने पर ज़ोर दिया।
- राज्यपाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला समानता के अवसर बढ़ाने, कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी कार्य करने, लैंगिक असमानता को रोके जाने के साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिये सैद्धांतिक ही नहीं, व्यावहारिक रूप से भी कार्य किये जाने की आवश्यकता जताई।
- इस अवसर पर राज्यपाल ने सम्मानित महिलाओं के सम्मान में प्रकाशित परिचय पुस्तक का भी लोकार्पण किया।

नोट :

मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनावों के लिये अपनी 5 बड़ी गारंटी लॉन्च करने की घोषणा की

चर्चा में क्यों ?

27 अक्तूबर, 2023 को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कॉन्ग्रेस वार रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिये अपनी 5 बड़ी गारंटी लॉन्च करने की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस लिस्ट में पहली गारंटी ओल्ड पेंशन स्कीम होगी। विदित हो कि 2022 में गहलोत ने राजस्थान में न्यू पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) लागू की थी। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था। अब मुख्यमंत्री गहलोत गारंटी देंगे कि उनकी सरकार आती है तो ओपीएस जारी रखेंगे।
- दूसरी गारंटी फ्री लैपटॉप की है। हालाँकि फ्री लैपटॉप की घोषणा गहलोत सरकार के इस कार्यकाल के बजट का हिस्सा थी, लेकिन यह योजना कागज़ों से आगे नहीं बढ़ी। अब मुख्यमंत्री गहलोत गारंटी देंगे कि सरकार आई तो सरकारी कॉलेज के छात्रों को फ्री लैपटॉप देंगे।
- तीसरी गो धन पशु गारंटी है। यह गारंटी छत्तीसगढ़ की कॉन्ग्रेस सरकार लॉन्च कर चुकी है। अब गहलोत सरकार भी गाँवों में पशुओं का गोबर और गो-मूत्र खरीदने की गारंटी देगी।
- चौथा अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल की गारंटी है। गौरतलब है कि गहलोत सरकार ने प्रदेश भर में अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल खोलने की योजना लॉन्च की थी। अब मुख्यमंत्री गहलोत इसे आगे बढ़ाकर पंचायत स्तर पर लागू करने की गारंटी देंगे।
- पाँचवी चिरंजीवी आपदा राहत की गारंटी है। गहलोत सरकार ने इस कार्यकाल में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की थी। इसमें प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। अब गहलोत इस योजना को आगे बढ़ाकर इसे आपदा राहत तक बढ़ाएंगे।

नोट :